पीपुल्स समाचार, भोपाल
22 APR 2010

जरूरी है यथा स्थितिवाद तोड़ना

अधिकारियों के थोक तबादले न किए जाएं, लेकिन यथा-स्थिति तोड़ने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं।

मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के थोक 61 अधिकारियों (आईएएस) के तबादले कर एक बड़ी प्रशासनिक शल्य चिकित्सा को अंजाम दिया। इस प्रशासनिक उठा-पटक में अधिकारी के पिछले पूरे कार्यकाल का लेखा-जोखा देखा परखा तो जाता ही है, यह भी तय किया जाता है कि भविष्य में यह अधिकारी किस तरह सरकार को गति देंगे। बड़े स्तर पर किए जाने वाले ये परिवर्तन दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। बड़े परिवर्तन के नाम पर कुछ और लक्ष्य होते हैं, जो सरकारें और नेता इससे पूरा करते हैं। इसीलिए ऐसे थोक प्रशासनिक परिवर्तन के कुछ और पहलू भी होते हैं।

सरकार के मुखिया के नाते शिवराज सिंह जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए भविष्य में भी जिम्मेदार होंगे। वैसे तो वह हर उस कदम के लिए जबावदेह हैं, जिसे उनकी सरकार के नाम पर उठाया जाता है। ये बात शिवराज के ही लिए नहीं बल्कि सत्ता प्रतिष्ठा से जुड़े हर जिम्मेदार के लिए लागू होती है। शिवराज सरकार एक संयत और शांत शासन की जैसे अपनी पहचान बना चुकी है। वह किसी आक्रमक बयानबाजी और ऐसे किसी फेरबदल में यकीन नहीं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जैसा व्यक्तित्व है, वही उनकी कार्यप्रणाली में झलकता है। उनके प्रशासन की छाप प्रदेश में साफ देखी जा सकती है। हाल ही में हुए बड़े कहे जाने वाले आइएएस अधिकारियों के तबादले एकाएक किए गए महसूस हो रहे हैं, लेकिन इसकी कवायद पहले से चल रही था। हां ये अवश्य महसूस हुआ कि थोक तबादलों का यह सबसे उपयुक्त समय था, जिसे शिवराज सिंह ने चुना। इन तबादलों से शिवराज सिंह ने बता दिया है कि आखिर उनका भी अपना प्रशासनिक सोच और दृष्टिकोण का अपना भी एक आयाम है। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने भी तबादले की बड़ी हलचल को पैदा करने से खुद को नहीं रोका। यह एक सामान्य प्रबंधन कौशल का उदाहरण भी है कि अधिकारियों के थोक तबादले न किए जाएं, लेकिन यथा-स्थिति तोड़ने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। ये कदम प्रशासनिक गतिशीलता के लिए आवश्यक होते हैं।